Development of horticulture sector

*20. SHRI BHUBANESWAR KALITA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India's share in the global horticulture sector has been increasing slowly but steadily and its production is set to rise 4 per cent during the current year;

(b) whether in spite of having vast scope and potential, the horticulture sector is still at a nascent state in the North-Eastern Region due to lack of infrastructure and poor and unfriendly policies of Government; and

(c) if so, whether Government would frame a policy for development of horticulture sector by providing adequate infrastructure, financial aid and support including incentives to the horticultural farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. SANJEEV KUMAR BALYAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) India's share in the global horticulture (fruits and vegetables) during the years 2011-12 to 2013-14 has been increasing, and its production is estimated to rise by 2.1% during the year 2014-15 (provisional). Details are given in Statement- I (*See* below).

(b) The share of area covered under horticulture crops and production in North Eastern States including Sikkim has been increasing steadily during the past three years. Details are given in Statement-II (*See* below). With improvement in horticulture sector, additional area has been brought under various horticulture crops besides creation of infrastructure facilities for improving the productivity, post harvest management, marketing and processing of horticulture produce.

(c) The scheme of Horticulture Mission for North Eastern and Himalayan States (HMNEH) under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), a Centrally Sponsored Scheme, is being implemented especially for holistic development of the horticulture sector in the North East (NE) and Himalayan States. HMNEH covers all the horticulture crops including fruits and vegetables. The HMNEH envisages production and productivity improvement of horticulture crops including fruit and vegetable crops through coverage of area with improved varieties, rejuvenation of

senile orchards, protected cultivation, creation of water resources, adoption of Integrated Pest Management (IPM), Integrated Nutrient Management (INM), organic farming, including *in-situ* generation of organic inputs. The Central Institute of Horticulture (CIH), Nagaland is engaged in capacity building of farmers and technicians for adopting improved technologies.

Statement-I

Table:1 : India's Share in Global Production of Fruits and Vegetables

(Production in Lakh Tonnes; India's Share in %)

Year	Total Production of Fruits and Vegetables		India's Share in Global Fruits and Vegetable Production
	World	India	
2011-12	17775.75	2327.50	13.1
2012-13	18059.37	2434.72	13.5
2013-14	18143.39	2574.07	14.2

Source: Indian Horticulture Database and Horticulture Statistics Division, DAC

Table-2: Growth Trends in Total Horticulture

(Production in Lakh Tonnes)

Year	India	Growth in Total Horticulture (in %)
2012-13	2688.5	
2013-14	2773.5	3.2
2014-15 (Provisional)	2832.1	2.1

Source : India: Horticulture Statistics Division, DAC

Statement-II

Table-3: Area and Production of Total Horticulture Crops in North East including Sikkim

A: Area in '000 Ha

P: Production in '000 Tonnes

State/UTs		Total Horticulture Crops					
		2012-13		2013-14		2014-15 (Provisional)	
Sl. No.		A	P	A	P	A	P
1.	Arunachal Pradesh	103.7	523.3	106.8	532.1	108.0	548.3
2.	Assam	626.0	5971.5	624.3	5546.3	646.2	6304.7
3.	Manipur	84.1	684.6	91.4	812.7	93.1	830.0

Sl.No.		A	P	A	P	A	P
4.	Meghalaya	113.6	823.9	122.1	979.0	123.8	1026.1
5.	Mizoram	120.3	761.2	130.0	835.8	143.2	950.9
6.	Nagaland	74.5	533.4	90.6	954.2	91.1	954.4
7.	Sikkim	67.0	243.1	74.4	232.3	77.0	237.8
8.	Tripura	126.2	1503.5	136.6	1617.1	124.4	1216.5
	TOTAL (North East)	1315.4	11044.3	1376.2	11509.4	1406.7	12068.7
	All India	23694.1	268847.5	24198.5	277352.0	24388.1	283210.4

Source: Horticulture Statistics Division, DAC

Table-4: Percentage share of North Eastern States in total area and production under horticulture crops

	State/UTs	Total Horticulture Crops (% share in All India)					
		2012-13		2013-14		2014-15 (Provisional)	
Sl. No.		A	P	A	P	A	P
1.	Arunachal Pradesh	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2
2.	Assam	2.6	2.2	2.6	2.0	2.6	2.2
3.	Manipur	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
4.	Meghalaya	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4
5.	Mizoram	0.5	0.3	0.5	0.3	0.6	0.3
6.	Nagaland	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3
7.	Sikkim	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1
8.	Tripura	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4
	TOTAL (North East)	5.6	4.1	5.7	4.1	5.8	4.3

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Mr. Chairman, Sir, I thank you. There is an encouraging growth in horticulture in this country. The growth in 2013-14 has been 3.2 per cent. The provisional growth this year is calculated as 3.2 per cent whereas the target has been kept at 4 per cent. Is the Government confident of achieving its target for the year 2014-15?

डा. संजीव कुमार बालियानः माननीय सभापति महोदय, टारगेट जरूर रखा गया था, लेकिन अभी तक जो प्रोविजनल फिगर्स आई हैं, वे 2.1 तक हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि इस वर्ष शुरू में सूखे की समस्या थी, पूरे देश में सूखा पड़ा और उसके बाद ओलावृष्टि, अतिवृष्टि हुई। ये जो समस्याएं थीं, उसके बावजूद अगर हम 2.1 पर हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन सब समस्याओं के बावजूद शायद हम 2.1 पर रहेंगे। मैं नहीं समझता कि शायद हम 4.0 परसेंट तक पहुंच पाएंगे।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, the horticulture mission has been announced for the North-Eastern Region and the hilly States. Many areas have been covered. In spite of that, we see a lot of damage due to lack of marketing, lack of cold storage facilities. Is the Government thinking of including marketing and creation of cold storage facilities into the mission?

डा. संजीव कुमार बालियानः माननीय सभापति महोदय, इसमें मार्केटिंग और स्टोरेज पहले से ही जुड़े हुए हैं। नॉर्थ-ईस्ट रीजन में जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटी है, काफी कम है। कई स्टेट्स तो ऐसी हैं, जहां एक ही कोल्ड स्टोरेज है। जहां तक मार्केटिंग का सवाल है, मार्केटिंग का क्वेश्चन अभी समाप्त हुआ है, उसमें मैंने लगातार बताया है कि पूरे देश में हम एक नेशनल मार्केट बनाने जा रहे हैं। नॉर्थ-ईस्ट की हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में जो सबसे बड़ी समस्या है, विशेष रूप से वह ट्रांसपोर्टेशन की है। सरकार का ध्यान लगातार उस ओर है और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी सरकार की मदद लगातार आ रही है।

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: Sir, I thank you very much. In relation to the development of horticulture, the answer given by the hon. Minister is an expression of a sense of complacency which is absolutely unacceptable to me. The point is, besides the stagnant share of fruits and vegetables in the world production of fruits and vegetables, two major challenges that are faced in this sector are the wastage and the lack of value addition.

Sir, India being the second largest producer of fruits and the third largest producer of vegetables, one-third of fruits and vegetables are wasted and not more than five per cent are processed. In order to overcome the agrarian crisis and help the farmers, will the Ministry give special consideration to increase the value addition, not just in raw forms, but even in taking sufficient and stronger steps to avoid the tremendous amount of wastage of fruits and vegetables, which is also contributing, in a way, to inflation during the seasonal variations? Thank you very much, Sir.

डा. संजीव कुमार बालियानः माननीय सभापति महोदय, हॉर्टिकल्चर में करीब 6 से 18 प्रतिशत तक का लॉस है, अगर वेल्यू में बात करें तो देश में करीब यह 44 हजार करोड़ रुपए बैठता है, जो स्टोरेज फैसेलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और मार्केटिंग की प्रॉब्लम की वजह से है। जहां तक माननीय सदस्य ने वेल्यू एडिशन की बात की है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड

प्रोसेसिंग एक अलग से मिनिस्ट्री है। जहां तक मार्केटिंग की बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, लॉस ज्यादा हैं, इन लॉस को कम करने का सरकार का ध्यान लगातार है।

श्री शरद यादवः श्रीमन, यह जो सवाल सब्जी को, फ्रूट्स को लेकर है, इसमें एक बात जरूर है कि ये सारे कोल्ड स्टोरेज और सारी चीजों का मंत्री जी ने बताया और जैसा फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का कह रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं है। यह विभाग सिर्फ दिल्ली में टिका हुआ विभाग है, उसमें कुछ काम नहीं होता। महोदय, एक तो मेरा कहना यह है कि इस मिनिस्ट्री को मजबूत कीजिए, तभी हम इस मामले को सुलझा सकते हैं।

महोदय, मेरी दूसरी बात यह है कि किसान सिर्फ कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं और सरकार ने स्कीम बनाई, तो उनसे वेयरहाउस बनवाए। वे ईंट के भट्टे बनाते थे और उन्हें कोई दूसरा धंधा नहीं आता है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं कि आज उनकी कितनी बुरी हालत हो रही है। उन्होंने किसी तरह से कर्ज लेकर के वेयरहाउस बना दिए।

यहां फूड प्रौसेसिंग की मिनिस्टर बैठी हुई हैं। वे खुद ही जानती हैं कि वह डिपार्टमेंट किस हालत में है। ...(**व्यवधान**)... नहीं आप हमारे बाद बोलिएगा।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः माननीय यादव जी, आप ऐसा मत कहिए। आपने पढ़ा ही होगा कि हाल ही में 17 नए मैगा फूड पार्क की कई हजार करोड़ रुपए की सैंक्शन सरकार की ओर से की गई है। इससे वेस्टेज को रोकने के जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इस दिशा में इन मैगा पार्कों का बहुत बड़ा योगदान होगा। अभी हाल ही में एक-दो हफ्ते पहले, कोल्ड चेन के लिए भी कई हजार करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। इसलिए पिछले 10 साल से जो नहीं हुआ था, उसे हम 10 महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह भी एंश्योर करेंगे कि टाइमली इनका इम्प्लीमेंटेशन जरूर हो। पहला स्टैप हमने ले लिया है और सैंक्शन कर दी है और अगला स्टैप इम्प्लीमेंटेशन का भी हम एंश्योर करेंगे और चार साल बाद आप यह जरूर कहेंगे कि वेस्टेज घटी है। इसलिए आप यह न कहें कि अब भी मंत्रालय वैसे ही डिफंक्ट पड़ा है। हां, पहले यह मंत्रालय डिफंक्ट जरूर पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है। ...(**व्यवधान**)...

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): सर, यह पुरानी स्कीम है और जब यू.पी.ए. गवर्नमेंट थी, तब यह स्कीम चली थी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, Sir ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Do you want to ask a question?

SHRI ANAND SHARMA: I want to ask a supplementary question.

MR. CHAIRMAN: One minute, please ...(*Interruptions*)... शरद जी, क्या आपका सवाल खत्म हो गया?

श्री शरद यादवः नहीं।

श्री सभापतिः शरद जी, कृपया सवाल को सवाल की तरह पूछिए।

श्री शरद यादवः महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा था, लेकिन मेरा सवाल उनकी तरफ चला गया। उस मंत्रालय के बारे में मेरी जानकारी थोड़ी पहले की है और आपने खुद ही मान लिया कि आपकी सरकार आने के बाद आपने इस कार्यक्रम को और इस डिपार्टमेंट को एक्सपीडाइट किया है। आप खुद ही मान रही हैं कि पहले यह डिफंक्ट था। मेरा असली सवाल बालियान जी से है।

मेरा सवाल यह है कि किसानों ने बैंकों से और अन्य जगहों से कर्ज लेकर वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं। यहां फूड मिनिस्टर बैठे हुए हैं। आप यह बताइए कि लोगों ने जो कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसेस बनाए हुए हैं, उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने उनसे बनवा तो लिया, लेकिन आज उनकी क्या हालत है, आपने सी.एल.यू. बना लिए हैं। इन लोगों ने Changed Land Use कर के उनसे वेयरहाउसेस और कोल्ड स्टोरेज बनवा लिए, अब उनकी खेती और जमीनों को बैंक अटैच कर रहे हैं। इसलिए मैं श्री बालियान जी से निवेदन करूंगा कि यह गंभीर मामला है और यह मामला भी किसानों का ही है। इसे ठीक करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसेस बनाए हैं, उनकी जमीनों और खेती को बैंकों द्वारा अटैच करने से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

डॉ. संजीव कुमार बालियानः माननीय सभापति महोदय, शरद यादव जी ने सवाल के रूप में जो कहा, वह चाहे वेयरहाउस हों या कोल्ड स्टोरेज, यह निश्चित रूप से जमीनी हकीकत है। जो नैशनल मार्केट की बात, हम पिछले एक घंटे से कर रहे हैं, अगर नैशनल मार्केट और ई-मार्केटिंग शुरू हो जाती है, तो जो कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसेस हैं, गवर्नमेंट की ओर से उनकी सर्टीफिकेशन की जाएगी, उसके माध्यम से यदि कोई भी किसान कोल्ड स्टोर अथवा वेयरहाउस में अपना सामान रखता है, तो उस सामान की ई-मार्केटिंग के द्वारा बिक्री हो सकती है। मुझे उम्मीद है, जैसे ही नैशनल मार्केट और ई-मार्केटिंग शुरू होगी, तो इन सबका सदुपयोग ज्यादा बेहतर तरीके से होगा।

श्री आनन्द शर्माः सर, अभी कुछ देर पहले सदन में माननीय मंत्री महोदय से यह बात कही गई कि भारत में फलों और सब्जियों का जो उत्पादन है, उसे मद्देनजर रखते हुए, फूड प्रोसेसिंग की और कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, जो अभी चर्चा में आई, क्योंकि कम से कम 35 से 40 प्रतिशत फसल खराब हो जाती है, न वह बाजार में आती है और न वह देश के बाहर निर्यात की जा सकती है। इसीलिए सरकार ने पहले भी और अभी भी इस बारे में निरन्तर कहा है कि इसमें सब्सिडी देना, इसमें कर्जा देना और साथ में राज्यों को भी समर्थन देना और 46 फूड पार्कों की स्थापना करना शामिल है। मेरा एक प्रश्न है कि इसमें निवेश के लिए, देश की पूंजी लगे, विदेश की भी पूंजी लगे और टेक्नोलोजी का भी इस्तेमाल हो, इन बातों को देखकर बहुत सोच-समझ कर निर्णय किया गया था कि फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमेंट, मल्टी ब्रांड रिटेल में हो। वह नोटीफाई कर दिया गया था। उस पर आपकी सरकार का क्या मत है, उस पर आपकी सरकार की चुप्पी है, उस पर हम जवाब चाहते हैं।

डा. संजीव कुमार बालियान : माननीय सभापति महोदय, आनन्द शर्मा जी बड़े सीनियर नेता हैं। उन्होंने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है, जिसका डायरेक्ट जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए इस सवाल का जवाब न देने के लिए मैं माफी चाहूंगा।

*21. [The questioner (SHRI K. N. BALAGOPAL) was absent.]